

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2346/2007/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मुरलीवाला एगोटेक, गुडली, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 75/रेस्टो/वेट/2007-2008 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.07.2007 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत पेश की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 61(2)(बी), 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.01.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी मक्का का आटा, केटलफीड, पुराना बारदाना, सातू, मुरमुरा, स्क्रेप, मिनरल्स, दलिया, पैकिंग मैटेरियल का निर्माता एवं विक्रेता है। आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिजली उत्पादन हेतु डीजल की खरीद कच्चे माल के रूप में किया जाना दर्शाते हुए आई.टी.सी. क्लेम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.01.2007 को पारित करते हुए डीजल की खरीद पर चाहे गये आई.टी.सी. को इस आधार पर अस्वीकार करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया कि डीजल की खरीद पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2007 से डीजल की खरीद पर आई.टी.सी. के बिन्दु पर स्वीकार करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।





लगातार.....2

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधि अनुसार पारित किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध है। कथन किया कि उनके द्वारा अपनी इकाई में बिजली उत्पादन हेतु डीजल का उपयोग किया जाता है, जो कि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक उत्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कच्चे माल पर आई.टी.सी. को रिवर्स किया जाना पूर्णतया विधि के विरुद्ध था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश के जरिये प्रत्येक बिन्दु की विवेचना करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुकूल है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के इस बिन्दु पर ही किये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिक निर्णयों से पूर्णतया आच्छादित है अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया।

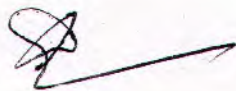
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में विवाद का एकमात्र बिन्दु यह था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी इकाई में बिजली के उत्पादन के लिये जो डीजल प्रयुक्त होता है उस पर वेट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) के अनुसार आई.टी.सी. का क्लेम अनुज्ञेय है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 2(29), 2(22) एवं 18(1)(ई) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

Sec. 2. Definitions.-

(22) **“manufacture” includes every processing** of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government;

(29) **“raw material” means** goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, **fuel and lubricant required for the process of manufacture;**



232

लगातार.....3

18. Input Tax Credit. -

(1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(e) **being used as raw material**, except those as may be notified by the State Government, **in the manufacture of goods** other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or

7. प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि व्यवहारी द्वारा डीजल का उपयोग बिजली उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है जो बिजली उत्पादन के लिये फ्यूल का कार्य करता है एवं कच्चे माल की उक्त परिभाषा धारा 2(29) में फ्यूल सम्मिलित है एवं वेट अधिनियम की धारा 18(1)(ई) में "विनिर्माण" कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर आई.टी.सी. अनुज्ञेय है। इस प्रकरण में यह विवाद है कि क्या इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिये जो डीजल कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह विनिर्माण हेतु कच्चा माल माना जावे या नहीं। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस बिन्दु पर पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल अपील संख्या 177 / 2007 वाणिज्यिक कर अधिकारी उदयपुर बनाम राजस्थान टैक्सकेम लिमिटेड निर्णय दिनांक 12.01.2007 का सुसंगत अंश उद्धरित किया जाना उचित होगा। सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"2. The above appeal filed by the Commercial Taxation Officer Circle-B, Udaipur raises a very interesting question of law of general public importance, as to the parameters for the test for the determination of raw materials and in addition to whether the use of articles or commodities not generally used in the manufacturing process can still be categorized as raw materials for the purpose of concession in the levy of taxes, for consideration by this Court. In other words; "Whether diesel can be called raw material in the manufacture of polyester yarn.

3. In the present case, the respondent is engaged in the business of manufacture of polyester yarn and for the said purpose, it purchased diesel and used it for manufacturing electricity by D.G.-sets. The respondent has claimed a benefit under Section 10(1) of Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') claiming that diesel purchased is a raw material for the manufacture of the ultimate final product - Polyester Yarn.



२११

लगातार.....4

.....

23. In view of the fact that the diesel is being used for the purpose of running the generator set for the production of the ultimate product which is also required for the purpose of manufacturing the end product the diesel can only be termed as raw material and not otherwise. The Rajasthan Tax Board was, therefore, justified in setting aside the orders passed by the Assessing Authority as confirmed by the Deputy Commissioner (Appeals).

.....

26. The respondent-assessee used diesel as raw material for the manufacture of the end product, namely, yarn and fabric. The diesel used by the assessee is a fuel and lubricant as defined under Section 2(34) of the RST Act."


8. माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी निर्माण कार्य हेतु आवश्यक बिजली के उत्पादन हेतु जो कच्चा माल कार्य में लिया गया है उसे अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु लिया गया कच्चा माल ही माना जायेगा। इस निर्णय में राजस्थान कर बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि पॉलिस्टर यार्न के विनिर्माण हेतु डीजल जनरेशन सेट में प्रयुक्त होने वाला डीजल, पॉलिस्टर यार्न के विनिर्माण हेतु कार्य में लिया जाने वाला कच्चा माल ही माना जावेगा।


9. इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ गुजरात बनाम एमी पिगमेंट्स प्रा० लि० (2009) वेट रिपोर्ट 61 में अवधारित किया है कि अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में प्रयुक्त किये गये फ्यूल जैसे Furnace oil, Naphtha, Liquid Diesel oil, Natural Gas आदि वस्तुएं अन्तिम उत्पाद के लिये कच्चे माल के रूप में ही सम्मिलित योग्य होंगे। इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से विधि स्थापित की जा चुकी है कि अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु पावर जनरेशन के लिये प्रयुक्त फ्यूल "कच्चे माल" की श्रेणी में ही सम्मिलित होता है अतः कच्चे माल के रूप में आई.टी.सी. देय होगी।

10. उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

11. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


(के. प्रब. जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य